(d) if so, what are the details in this regard and the total quantity of such coal supplied by the collieries to the steel plants during the current financial year upto October, 1991?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV); (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. During 1991.92, while, Visakhapatnam Steel Project's (VSP) dependence on indigenous coal is nominal, SAIL plants' efforts will be directed at efficient management of indigenously available and imported coal so as to ensure that their production programme does not suffer.

(c) and (d) As against the desirable ash content of 17 per cent and the agreed ash norm of around 19 per cent (weighted average in the blend) for 1991-92 for SAIL plants, the ash content in the indigenous coking coal fluctuated between 19.8 per cent and 20.3 per cent during the months April-October, 1991. Total quantity of coking coal received by SAIL's steel plants and VSp during this period from Coal India Limited was 48.4 lakh tonnes and 2.75 lakh tonnes respectively.

Modernisation of Durgapur Steel Plant

2409. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the former Chairman-cum-Managing Director of SAIL and Maruti Limited after retirement in 1990, has set Up companies worth hundreds of crores of rupees;

(b) whether it is also a fact that the official still resides in Government accommodation in Delhi;

(c) whether it is also a fact that the officers involved in a fraud of hundreds of crores of rupees in the modernisation of Durgapur Steel Plant are still holding important posts in SAIL and continue to defraud the Authority;

(d) whether it is a fact that Government had sanctioned Rupees 1360 crores for the modernisation of Durgapur Steel Plant on the 24th September, 1986 and the same amount was stepped upto Rs. 2668 crores in 1988, and if so, the reasons for stepping up the amount, and the names of officers responsible therefor; and

(e) the basis for awarding a contract for Rupees 461 crores, out of rupees 2662 crores, to the Birla Technical Services?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) Government of India sanctioned on September 24, 1987, the scheme for the Renovation and Technological Upgradtion (Modernisation), of Durgapur Steel Plant of Steel Authority of India Limited at a tentative cost estimate of Rs. 1357 crores (base 3rd quarter 1986 prices) inclusive of a foreign exchange component of Rs. 437 crores. The estimates were to be firmed up within 12 months from the date of approval of the scheme after tenderig action was completed. Accordingly, a Definitive Cost Estimate, based on tenders, of Rs. 2667.6 crores (base 3rd quarter 1988 prices) inclusive of a foreign exchange component of Rs. 685 crores was sanctioned by Government on February 20, 1989. The increase in cost was on account, *inter-alia* of monetary reasons like change in foreign exchange parity, duties and taxes and escalations in prices since 3rd quarter, 1986, besides change in scope and quantities. No specific instance of fraud Has come to the notice of the Government in the case of Durgapur Steel Plant Modernisation work where hundred of crores of rupees were involved. Officers of SAIL who were responsible for the work relating to DSP modernisation project, depending on their age and dates of retirement, are still serving or have since retired,

(e) Steel Authority of India Ltd. had awarded four global contracts to the leaders of the Consortium whose prices were the lowest. M/s. Birla Technical Services (BTS) were members of these Consortia. SAIL had found Mls. BTS competent.

मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा स्क्रैप का आयात

2410. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् उक्त निगम को क्या-क्या नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि देश के छोटे-छोटे इस्पात संयंत्रों को आयातित स्क्रैप उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस निगम की है ;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश के छोटे इस्पात संयंत्रों की स्क्रैप की कितने प्रतिशत मांग निगम द्वारा पूरी की गई ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि छोटे इस्पात संयंत्रों के प्रतिनिधियों ने इस आशय के अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं कि निगम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में समर्थ नहीं था, यदि हां, तो निगम को और अधिक जिम्मेदारियां सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड को कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है ।

(ग) कार्बन इस्पात प्रगलन स्क्रैप का आयात करने के लिए मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन एक माध्यम एजेंसी है । फिर भी, प्रयोक्ता उद्योग भी स्क्रैप का आयात निर्यात आयात पत्र (पहले आर. ई.पी. लाइसेंस) के माध्यम से सीधे करते हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम.एस.टी.सी. द्वारा स्क्रैप की पूरी की गई पंजीकृत मांग का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

वर्ष	एमएसटीसी द्वारा पूरी की गई पंजीकृत मांग का प्रतिशत
1988–89 . .	45.14
1989–90 . .	25.57
1990–91 . .	33.00

इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ता उद्योग भी आर. ई. पी./लाइसेंस और सीधे लाइसेंस के माध्यम से सीधे आयात करते हैं।

(ङ) स्क्रैप की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में स्टील फर्नेस एशोसिएशन आफ इंडिया और अलग-अलग यूनिटों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । पर्याप्त विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता के कारण एमएस टी सी प्रयोक्ता उद्योगों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका । फिर भी इस प्रकार के उद्योग भी आर. ई. पी./लाइसेंस (अब निर्यात-आयात पत्र) और सीधे लाइसेंस के माध्यम से स्क्रैप का सीधे आयात कर सकते हैं।

छोटे इस्पात संयंत्रों की समस्याएं

2411. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर 1991 के फाईनेंशियल ऐक्सप्रैस